Statement- III

Investment in agriculture sector (At constant 1980-81 *prices)*

Year	Public Sector	Private Sector	Total
Seventh Plan			
1985-86	1520	2805	4325
1986-87	1425	2586	4011
1987-88	1458	2956	4414
1988-89	1362	2985	4347
1989-90	1156	3197	4353
Annual Plans			
1990-91	1153	3449	4593
1991-92	1001	3496	4497
Eighth Plan			
1992-93	1065	3552	4617
1993-94*	1074	3621	4695

(in Rs Crores)

Quick Estimates

PNK Rice Varieties

1687. HRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that PNR rice varieties developed at Indian Agricultural Research Institute (IARI) have given a boost to rice revolution in the country;

(b) if so, the details of the new varieties developed;

(c) whether it is also a fact that the benefits of rice revolution has remained confined to one third of the failing community of the country;

(d) whether Government have contemplated to extend the benefits of rice revolution to the remaining section of the farming community of the country: and

(e) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and lb) The rice varieties PNR 381 and PNR 162 developed at Indian Agricultural Research Institute (IARI) have been performing well in upland rainfed of the country and irrigated areas of Uttar Pradesh respeclively.

(c) to (e) The benefits of rice revolution have by and large reached all over the country. However, areas endowed with resoures have benefitted more. The farming community is getting the benefits of rice revolution through on going schemes of Integrated Cereal Development and Minikit programmes of Government of India,

कृषि अनुसंधान के लिए आवंटित धनराशियां

1688. श्री अनेश्वर मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशियां आवंटित की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने 81वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशों पर गठित किए गए कार्यदल की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के उपाय किए हैं; और

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) चालू वर्ष 1994-95 में अनुसंधान के लिए 274.99 करोड़ रु० और विकास के लिए 1803.62 रु० का आवंटन (संशोधित आकलन) किया गया है ।

(ख) और (ग) जी, हां । की गई/शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 81 वें सत्र की सिफारिशों पर भा०कृ०अ० परिषद/कृ०अनु०शि० विभाग की प्रतिक्रिया

संख्या	सिफारिशें	भा० कृ० अ० प०/ कृ० अ० शि० वि० की० प्रतिक्रिया
1.	शैक्षणिक पद्धतियों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करने होंगे ।	कृषक समुदाय को सीधे लाभ पहुंच सके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान विस्तार-शिक्षा और कृषि शिक्षा हेतु भा० कृ० अ० परिषद के अनुसंधान संस्थानों का राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ काफ़ी संबंध है, बीज, उर्वरक कीटनाशक रसायनों और कृषि उत्पादों को आगे बढ़ाने के काम में लगे निजी बीज क्षेत्र एवं कृषि उद्योगों के साथ भी इसके संबंध हैं ।
2.	विज्ञान और टैक्नोलाजी कार्मिकों को दूसरे देशों से भारत में टैक्नालाजी हस्तांतरण पर लगे प्रतिबन्ध पर ध्यान रखना चाहिए और मौके के मुताबिक काम करना चाहिए ।	भारत में विदेशी टैक्नोलाजी का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में हस्तांतरण यथोचित जांच और केवल अनुमोदित द्विपक्षीय कार्यक्रमों के तहत ही किया जाता है । खेतों में प्रयोग में लाने से पहले स्थान विशेष के लिए उपयुक्तता के आधार पर इनमें सुधार किया जाता है ।
3.	एस. एवं टी. में निवेशों को सरकार व उद्योग दोनों द्वारा बढ़ाना होगा ।	परिषद इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ।

संख्या	सिफारिशें	भा० कृ० अ० प०/कृ० अ० शि० वि० की प्रतिक्रिया
8.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट में आमतौर पर जो कुछ प्राप्त किया है उसकी उज्जवल तस्वीर ही दी जाती है। वैज्ञानिक संगठन को जो वे करना चाहते हैं उसे और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जा सकता है, उसका भी उल्लेख करना चाहिए।	भा० कृ० अनु० प० की वार्षिक रिपोर्ट में, वर्ष के दौरान किए गए कार्यों और प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। प्रायोजनाओं को पूरा करने में आ रही रुकावटों और वार्षिक कार्यक्रम में भविष्य में अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्रों को भी दर्शाया जाता है। इसके अलावा इस संस्था को भविष्य में सुदृढ़ करने और उसे पुनर्गठित करने के लिए भी परिषद एक भावी योजना तैयार कर रही है।
14.	यह भी जरूरी है कि जिन पोस्ट डाक्टोरल फैलोज रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों और सम्पर्क अधिकारियों की सेवाओं का विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा लम्बे समय तक उपयोग किया गया है, प्रायोजना की समाप्ति के बाद उन्हें यों ही बेकार नहीं छोड़ देना चाहिए।	पोस्ट डाक्टोरल फैलोज, अनुसंधान वैज्ञानिक और सम्पर्क अधिकारी, जिन्होंने भा० कृ० अनु० परिषद/कृ० अनु० शि० वि० के लिए कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों में कार्य किया है उन्हें कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु उसमें भाग लेने का विकल्प प्राप्त है।
30.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रायोजना को ठोस प्रायोजना शुरू करनी चाहिए जिसमें विश्वविद्यालयों के सांख्यिकीय विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है।	भा० कृ० अ० प० के अनुसंधान प्रयोगशालाओं को पर्याप्त सांख्यिकीय सहायता प्राप्त है और कम्प्यूटरीकरण की सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।
31.	प्रायोगात्मक कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाओं और औजार बनाने वाले उद्योगों में औजारों को बनाने और तैयार करने पर विशेष बल देना चाहिए।	कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को इस कार्य के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।
34.	पशु पालन और पशुधन के विकास के लिए देश में एक नोडल एजेन्सी स्थापित की जाए।	कृषि मंत्रालय में पशु पालन और पशुधन के विकास के लिए पशु पालन एवं डेयरी का एक अलग विभाग बनाया है जिसके लिए भारत सरकार के एक पूर्ण कालिक सचिव की नियुक्ति की गई है और यह विभाग एक केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में काम करता है।